भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2604

जिसका उत्तर 04 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

कोयला खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2604. सुश्री नुसरत जहां रूही:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कोयला खनन में शत–प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ–साथ ऑटोमेटिक रूट के आल थ्रो ठेका विनिर्माण में शत–प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को देश की विभिन्न कोयला यूनियनों से इस निर्णय के विरुद्ध कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस कदम का कोल इंडिया लिमिटेड जोकि एक राष्ट्रीय कोयला खान है, पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ) : सरकार ने दिनांक 18.09.2019 को कोयला खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा की है जिसमें संबद्ध प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कोयले की बिक्री, कोयला खनन संबंधी क्रियाकलापों के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है जो समय-समय पर संशोधित कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के उपबंधों और इस विषय से संबंधित अन्य अधिनियमों के अधीन होगी। संबद्ध प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कोल वॉशरी, कोयले की हैंडलिंग और सेपरेशन (मैगनेटिक और नॉन-मैगनेटिक) शामिल हैं। कोयले की बिक्री के लिए संबद्ध प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कोयला खनन संबंधी क्रियाकलापों के लिए 100% एफडीआई की अनुमति से आशा है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आकर्षित होंगी और दक्षतापूर्ण तथा प्रतिस्पर्धात्मक कोयला बाजार तैयार होगा।

विभिन्न केन्द्रीय व्यापार संघों (सीटीयू) ने कोयले की बिक्री हेतु ऑटोमेटिक रूट से कोयला खनन और संबद्ध प्रोसिस में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने के सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सभी सहायक कंपनियों में काम रोकने के लिए हड़ताल का नोटिस दिया था।

भारतीय कोयला बाज़ार में एफडीआई राष्ट्र की ऊर्जा-आवश्यकताओं को पूरा करने के सीआईएल के प्रयासों में सहायक होगी है। इस तरह राष्ट्र को नई प्रौद्योगिकी और विश्वस्तरीय श्रेष्ठ पद्धतियों का लाभ मिलेगा जो कि सीआईएल के लिए भी फायदेमंद होगा। सीआईएल का अनुभव और इसकी मूल क्षमता इसे अधिक लागत नियंत्रण और परिचालन दक्षता के साथ प्रतिस्पर्धा में आगे रखेगी।

*****